सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 05, मंगलवार, *शाके* 1945-अप्रेल 25, 2023 *Vaisakha 05, Tuesday , Saka 1945- April 25, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 22, 2023

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

संख्या 4336 :- राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (गुरप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 1469 दिनांक 03.11.2022 के निर्देशानुसार **Consultancy Services for Social Impact Assessment Study for the purpose of Acquisition of land for highway/road project on Butati (NH-89) to Jobner (SH-90) via-Bachhwari-Jalsu-Degana-Gachhipura-Harnawa-Badu-Parbatsar-Bhervai-Ujoli-Bhadoon-Chhapri-Shakambhari-Sambhar Km 49/0 to 103/0 (SH-135) in accordance with the Rajasthan as per RFCTLARR (Rajasthan Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilition and Resettlement Rule.)** के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील परबतसर एवं मकराना, जिला-नागौर में निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांव	सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	नागौर	परबतसर	(1) बडू (2) माण्डण	उपखण्ड अधिकारी परबतसर
2	नागौर	मकराना	(1) इटावाखिंचीया (2) ईटावाबामणिया	उपखण्ड अधिकारी मकराना

अतः राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन उक्त भूमि के सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु नियमानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड परबतसर जिला नागौर द्वारा सलाहकार ए आर इंटरनेशनल कन्सलटेन्सी (श्री कमलेश कुमार शर्मा एवं श्रीमति योगिता कुमावत-सोशल एक्सपर्ट) 69 नालन्दा विहार महारानी फॉर्म दुर्गापुरा जयपुर-302018 मोबाईल-9799899347, 8949844589 एजेन्सी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगाः

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्षित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।
3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 8 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड परबतसर
जिला-नागौर

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

ए आर इंटरनेशनल कन्सलटेन्सी
(श्री कमलेश कुमार शर्मा-सोशल एक्सपर्ट)
मोबाईल: 9799899347
(श्रीमति योगिता कुमावत-सोशल एक्सपर्ट)
मोबाईल: 8949844589
69 नालन्दा विहार, महारानी फार्म,
दुर्गापुरा, जयपुर-302018

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।